RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2016-2018 IPT indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 11 APRIL TO 17 APRIL 2018 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 03 ■ अंक 33 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

पांच राज्यों में अंदरुनी व्यापार के लिए E-WAY बिल 15 अप्रैल से जरुरी

Page 3

RBI की रोक के बाद, भारत छोड़ने की तैयारी में बिटकॉइन एक्सचेंज

Page 4

भारतीय रेल को मिला सबसे पॉवरफुल इंजन, बढ़ जायेगी गाड़ियों की रफ्तार

Page 7

editoria!

टकराव का कारोबार

अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। शुरू में लगा कुछ मसलों पर मतभेद उभर आए हैं जो आपसी बातचीत से सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों पक्ष ज़िद पर अड़ गए हैं। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि अगर चीन ने व्यापार करने के अपने तरीकों में बदलाव नहीं किया तो वह उस पर 100 अरब डॉलर का टैरिफ लगा देंगे। इससे पहले बुधवार को चीन ने 50 अरब डॉलर मूल्य के 106 अमेरिकी उत्पादों के आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया। मार्च में ट्रंप ने चीन से आयात पर 60 अरब डॉलर यानी 3910 अरब रुपए का टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इससे बौखलाए चीन ने भी उन अमेरिकी उत्पादों की लिस्ट जारी की, जिन पर वह भारी-भरकम आयात शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल ट्रंप की धमकी के बाद चीन ने शुक्रवार को कहा कि वह अमेरिका के कदमों के मुहतोड़ जवाब देगा। अमेरिका ने अब तक कई बार चीन पर टैरिफ लगाया है। उसका तर्क है कि चीन गैर-कानूनी तरीके से व्यापार करता है और उसकी इन गतिविधियों ने अमेरिका में हजारों लोगों की नौकरियां छीन ली हैं। ऐसे में अपने व्यापार को बचाने के लिए उसे यह सही कदम लगता है। अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिका ने पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है। जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है, उनका ध्यान सिर्फ अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने पर रहता है। वे यह भूल गए हैं कि अमेरिका की अगुआई में ही दुनिया ने उदार अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण की ओर कदम बढ़ाए हैं। आज वैश्विक कारोबार की दिशा को अचानक पीछे की ओर लौटाया नहीं जा सकता। ट्रेड वॉर से विश्व में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक विकास कम होगी और ट्रेडिंग साझेदार देशों के रिश्ते बिगड़ेंगे। इस टकराव का एक कूटनीतिक पहलू भी है। चीन को इस प्रकरण में रूस का साथ मिल रहा है। दोनों देश आपसी संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को सुधारने की कोशिश में हैं और ट्रेड वॉर में भी वे अमेरिका के खिलाफ एकजुट हैं। इस कारोबारी टकराव का भारत पर सीधा असर भले न हो, लेकिन परोक्ष रूप से अर्थव्यवस्था प्रभावित जरूर होगी। एसोचैम का कहना है कि भारत अगर अपना आयात संभाल लेता है तो भी निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट्स भी बढ़ेंगे। विश्व बिरादरी को इस मामले में मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए। उसे चीन और अमेरिका दोनों पर दबाव डालकर इस टकराव को समाप्त करने की पहलकदमी करनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन और अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष जैसी संस्थाएं भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं।

कच्चे तेल में आया उबाल

कीमतें 2014 के बाद उच्चतम स्तर पर, ये हैं बड़े कारण

नई दिल्ली। आईपीटी न्यूज

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें अगर आपको परेशान कर रही हैं तो फिलहाल किसी बड़ी राहत की उम्मीद न लगाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बीते तीन साल में सबसे ऊपरी स्तर पर है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में यह तेजी आने वाले सत्रों में भी जारी रहेगी और ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को छू सकता है। गौरतलब है कि मंगलवार को ब्रेंट क्रूड 3 फीसद के उछाल के साथ 71.34 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया, जो 2014 के बाद अब तक का सबसे ऊपरी स्तर है।

विशेषज्ञ का नजरिया

जानकारों के मुताबिक मौजूदा अंतराष्ट्रीय परिदृश्य में कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट देने वाले कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रहने की पूरी संभावना है। इस तेजी में ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल तक के स्तर छू सकता है।

इस तेजी के कारण बताते हुए कहा जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच छिड़ा ट्रेड वार और रूस और ओपेक देशों की ओर से कच्चे तेल की सप्लाई को जानबूझकर बाधित करना समेत कई फैक्टर्स कीमतों को सपोर्ट दे रहे हैं। उनके मुताबिक बुधवार को अमेरिका में जारी होने वाले इंवेंट्री के आंकड़ों से पहले कच्चे तेल की कीमतों में यह तेजी बनती है। इंवेंट्री का लगातार घटना भी कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट दे रहा है।

एक अन्य जानकार का भी मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का बड़ा कारण जियो पॉलिटिकल टेंशन ही है। इसके कम होने या बढ़ने से ही कच्चे तेल की कीमतों में आगे की दिशा तय होगी। होगी फिलहाल 75 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर अहम है इसके टूटने पर कीमतें 80 डॉलर के स्तर तक जा सकती हैं।

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण

जियो पॉलिटिकल टेंशनः खाड़ी देशों में तनाव का बढ़ना कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सबसे बड़ा कारण है। यूरोप की एयर ट्राफिक कंट्रोल एजेंसी ने अगले अगले 72 घंटों में सीरिया पर एयर स्ट्राइक की आशंका जताई है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में एकाएक उबाल आया है और कीमतें कई साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

ट्रेड वार : अमेरिका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वार में चीन की ओर से नरमी के संकेत दिए गए हैं, जो कच्चे तेल में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है। रवि ने यह भी कहा कि ट्रेड वार में इम्पोर्ट टैरिफ जिन वस्तुओं (मेटल और एग्री) पर लगाए जा रहे हैं वे अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता को हवा देता है जो कच्चे तेल के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है।

देश के सबसे बड़े उत्पादक समूह ओपेक और रूस मिलकर कच्चे तेल की सप्लाई को बाधित कर रहे हैं। जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के ऑर्डर में भी देरी देखने को मिली है। कच्चे तेल की डिमांड और सप्लाई में इस आर्टिफीशियल तरीके बाधित करने की वजह भी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी इसका साफ संकेत है। अमेरिका, भारत समेत दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं का वापसी लंबी अवधि में कच्चे तेल की कीमतों तो सपोर्ट देता है।

महाराष्ट्र रिफाइनरी की 50 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी सऊदी अरामको

नई दिल्ली। आईपीटी न्यूज

दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अरामको महाराष्ट्र की रिफाइनरी में 50 फीसदी हिस्सेदारी 44 अरब डॉलर में खरीदेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ) के यहां हो रहे सम्मेलन से इतर इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सऊदी के तेल मंत्री खालिद ए.अल-फालिह ने कहा कि सऊदी निवेश के लिए भारत एक महत्वपूर्ण गंतव्य है और अरामको इस रिफाइनरी से इतर भी अन्य अवसरों की तलाश करेगी। सऊदी अरब छह करोड़ टन की क्षमता की इस रिफाइनरी के लिए 50 फीसदी तेल की आपूर्ति करेगा। इस परियोजना में बाकी की हिस्सेदारी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रहेगी।

इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की बैठक का उद्घाटन करेंगे पीएम

नई दिल्ली। एजेंसी

कुछ वर्ष पहले की बात है जब भारतीय पेट्रोलियम मंत्री को तेल एवं गैस उत्पादन करने वाले बड़े देशों के संबंधित मंत्रियों से मिलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। हालात अब बदल गए हैं।

कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और भारत की तेज आर्थिक विकास दर को देखते हुए ये तमाम देश अब भारतीय पेट्रोलियम मंत्री से मिलने का कोई मौका नहीं गंवाते। बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो रही इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की बैठक में शामिल होने के लिए 92 देशों के प्रतिनिधियों में से अधिकांश देश भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने की मंशा जता चुके हैं। ऊर्जा उत्पादक एवं उपभोक्ता देशों की यह सबसे बड़ी बैठक है। सऊदी अरब, ईरान, नाइजीरिया, अल्जीरिया और रूस जैसे देश भारत को ज्यादा तेल व गैस बेचने की इच्छा रखते हैं तो नॉर्वे और अमेरिका जैसे बेहद उन्नत देश भारत को इस क्षेत्र की हर तकनीक उपलब्ध कराने को तैयार हैं। मंगलवार को इनमें से कई देशों के ऊर्जा एवं पेट्रोलियम मंत्रियों ने भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंतरराष्ट्रीय फोरम का उद्घाटन करेंगे। इसमें अरबों डॉलर के कारोबार व निवेश सौदों को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह सभी देशों को एक मौका देगी कि किस तरह दुनिया में ऊर्जा से जुड़े मुद्दों का एक सर्वमान्य हल निकाला जाए। फोरम के 72 देशों के अलावा 20 और देशों को भी बतौर मेहमान आमंत्रित किया गया है। भारत इस बैठक से प्रमुख तौर पर दो तरह से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। पहला, कच्चे तेल के बड़े उत्पादक देश भारत समेत अन्य एशियाई देशों को प्रीमियम दर पर तेल बेचना बंद करें। दूसरा, जिस तेजी से भारत अपनी अर्थव्यवस्था को गैस आधारित बना रहा है उसके लिए दूसरे देशों से पर्याप्त मात्रा में गैस हासिल करने की राह खुले। बैठक से ठीक पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से एक अध्ययन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत के तेल व गैस क्षेत्र में कुल 325 अरब डॉलर का निवेश होगा। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में अगले 10 वर्षों में 150 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। फोरम के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल उत्पादक देशों के साथ अलग से भी आपसी ऊर्जा संबंधों पर बातचीत होगी। मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक के महासचिव मोहम्मद बारकिंडो के साथ मुलाकात में कीमत का मुद्दा उठाया। उन्होंने गैस निर्यात करने वाले देशों के संगठन जीईसीएफ के महासचिव यूरी सेंतायरीन से भी भेंट की।

भारत अपने मजबूत होते कद का इस्तेमाल कच्चे तेल के लिए बेहतर मोलभाव में करेगा

नई दिल्ली। एजेंसी

इस सप्ताह ऊर्जा मंत्रियों के इंटरनैशनल कॉन्फ्रेंस में द्विपक्षीय बैठकों के दौरान भारत की नजरें सऊदी अरब समेत प्रमुख तेल उत्पादकों के साथ जबरदस्त मोल-भाव करने पर है। अधिकारियों ने बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है और वह मोल-भाव में अपनी इस हैसियत को भुनाने की कोशिश करेगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक अधिकारी और सरकारी तेल कंपनियों के 2 अधिकारियों ने बताया कि इस सप्ताह होने वाले इंटरनैशनल एनर्जी फोरम में भारत को सऊदी अरब और नाइजीरिया से कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारत इस सप्ताह होने वाले इंटरनैशनल एनर्जी फोरम की चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ सह-मेजबानी कर रहा है।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा, 'दुनिया भारतीय बाजार के आकार और इसकी खपत को अच्छी तरह समझती है। हम चाहते हैं कि आपूर्तिकर्ता भारत के प्रति पहले के मुकाबले और अनुकूल दृष्टिकोण दिखलाएं। हम चाहते हैं कि समझौते और ज्यादा पारदर्शी व न्यायपूर्ण हों।'

इस तरह की मांगें ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ की बड़ी ताकत के तौर पर भारत के नए आत्मविश्वास को दर्शाती हैं। एक विशेषज्ञ ने बताया कि अब भारतीय अधिकारी जब ऐसे समिट्स में जाते हैं तो तेल उत्पादकों से और इन्सेंटिव की मांग करते हैं, जो बड़ा बदलाव है। भारत को कुछ रियायतें मिलने भी लगी हैं। ईरान ने भारतीय सरकारी रिफाइनरों को फ्रेट प्राइसेज में डिस्काउंट बढ़ाने की पेशकश की है। सऊदी एरैमको ने पिछले साल कुछ भारतीय रिफाइनर्स के लिए क्रेडिट लिमिट बढ़ा दिया है ताकि वे बिना किसी बड़ी फाइनैंशल गारंटी के और ज्यादा कच्चा तेल उठा सकें।

भारत और बांग्लादेश के बीच तेल पाइपलाइन समझौता

भारत हर साल देगा 10 लाख टन कच्चा तेल

ढाका। एजेंसी

बांग्लादेश और भारत ने प्रस्तावित 129.5 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन से संबंधित समझौते पर ढाका में हस्ताक्षर किए है। इस पाइप लाइन से भारत से बांग्लादेश को सालाना 10 लाख टन कच्चे तेल की आपूर्ति की जाएगी। एजेंसी की खबरों के अनुसार, यह सौदा बांग्लादेश और भारत के बीच हुए छह समझौता प्रस्तावों में से एक है। इस समझौते पर ढाका में दोनों देशों के विदेश सचिवों ने हस्ताक्षर किए। दोनों विदेश सचिवों ने इस मौके पर भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी रिश्ते को और बेहतर करने पर भी जोर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने तीस्ता जल बटवारे मुद्दे और रोहिंग्या शरणार्थी संकट पर भी चर्चा की। विदेश सचिव विजय गोखले और बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद शाहिदुल हक ने द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा की और आपसी हितों के मुद्दों पर अपने-अपने देशों का पक्ष रखा। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में यह जानकारी दी। इससे पहले भारत के विदेश सचिव विजय केशव गोखले, वरिष्ठ बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करने रविवार को यहां पहुंचे। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद गोखले ने कहा, 'बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की हाल ही में भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हस्ताक्षरित सार्थक समझौतों की सूची में आज हमने छह अन्य दस्तावेज जोड़े हैं।' बताया जा रहा है कि इन दस्तावेजों में नूमलीगढ़ और परबातीपुर के बीच पाइपलाइन पर एमओयू का कार्यान्वयन, प्रसार भारती और बांग्लादेश रेडिओ के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन, ढाका विश्वविद्यालय में आईसीसीआर उर्दू पीठ की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन और जीसीएनईपी-बीएईसी इंटरएजेंसी एग्रीमेंट शामिल है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने दो और परियोजना समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें बांग्लादेश के 500 स्कूलों में लैब की स्थापना के साथ ही बांग्लादेश के रंगपुर शहर के विभिन्न सड़कों का पुनःनिर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं के चलने दोनों देशों के संबंध और भी प्रगाढ़ होने की आशा जताई जा रही है।

ईरान से दोगुना तेल आयात करेगा भारत

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत सरकार क्रूड आयल कच्चा तेल बेचने के लिए ईरान द्वारा की गई इंसैंटिव की पेशकश को भुनाने के मूड में है। इस क्रम में सरकारी रिफाइनरियों ने वित्त वर्ष 2018-19 में ईरान से तेल आयात इम्पोर्ट दोगुना करने की योजना बनाई है। वहीं ईरान ने तीसरे बड़े ऑयल इम्पोर्टर देश में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए यह ऑफर दिया है।

ईरान एशिया में अपने ऑयल कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए सऊदी अरब जैसे अन्य अरब देशों की तुलना में आकर्षक शर्तों की पेशकश कर रहा है। ईरान ने हाल में ज्यादा खरीद पर भारतीय कम्पनियों को फ्रेट पर डिस्काऊंट ऑफर किया था। भारत के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि वह चीन के बाद ईरान का दूसरा बड़ा क्लाइंट है।

अमरीकी प्रतिबंधों के बाद ईरान से घटा था इम्पोर्ट

अमरीकी प्रतिबंधों से पहले ईरान, भारत के लिए दूसरा बड़ा ऑयल सप्लायर देश था जिसके बाद 2016-17 में वह सऊदी अरब और ईराक के बाद तीसरे पायदान पर आ गया था। हालांकि अब प्रतिबंध हटने के बाद ईरान धीरे-धीरे भारत में अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है।

तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है ईरान

2017-18 के आधिकारिक आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल, 2017 से फरवरी, 2018 के बीच ईरान के लिए भारत तीसरा बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर रहा। वहीं ईराक सऊदी अरब को पछाड़कर भारत के लिए सबसे बड़ा सप्लायर बन गया।

3.96 लाख बैरल प्रतिदिन ऑयल के इम्पोर्ट की बनाई योजना

इस डिवैल्पमैंट की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि सरकारी रिफाइनर्स इंडियन ऑयल कॉर्प, मंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, भारत पैट्रोलियम और ह्क्षहदुस्तान पैट्रोलियम ने अप्रैल, 2018 से शुरू हुए वित्त वर्ष के दौरान ईरान से 3.96 लाख बैरल प्रतिदिन बी.पी.डी. ऑयल के इम्पोर्ट की योजना बनाई है। हालांकि इस मसले पर इंडियन ऑयल, मंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स, भारत पैट्रोलियम और हिंदुस्तान पैट्रोलियम ने कोई प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया। इन चारों रिफाइड्क्षनग कम्पनियों ने पिछले वित्त वर्ष में ईरान से लगभग 2.05 लाख बी.पी.डी. ऑयल का इम्पोर्ट किया था।

सरकार ने क्रूड ऑयल पर फोड़ा पैट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम का ठीकरा

जी.एस.टी. में भी लाने को तैयार

रायपुर। सरकार ने देश में बढ़ती पैट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों का ठीकरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर फोड़ा है। पैट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में इजाफा होता है, तो भारत में भी पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में पहले पैट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हुए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने से यहां पर पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ौतरी हुई है।

इसके साथ ही उन्होंने लगे हाथ सरकार की मंशा को जाहिर करते हुए कहा कि उनका मंत्रालय यह चाहता है कि पैट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवाकर जी.एस.टी. के दायरे में लाया जाए। पैट्रोलियम मंत्री ने कहा कि हालांकि यह विषय रहता है कि पैट्रोलियम पदार्थ पर इतना टैक्स क्यों है। पैट्रोलियम मंत्रालय जी.एस.टी. काऊंसिल को बार-बार अनुरोध कर रहा है तथा सुझाव दे रहा है कि जी.एस.टी. काऊंसिल इस विषय पर निर्णय करे कि पैट्रोलियम पदार्थ भी धीरे-धीरे जी.एस.टी. के अंतर्गत आ जाए। प्रधान ने कहा कि राज्यों में भी धीरे-धीरे मन बनाया जा रहा है। शुरुआत में जी.एस.टी. के स्वरूप और राज्य की आय को लेकर चिंता थी, लेकिन धीरे-धीरे जी.एस.टी. की सफलता सामने है। पैट्रोलियम मंत्रालय चाहता है कि पैट्रोलियम पदार्थ भी जी.एस.टी. के दायरे में आएं।

समुद्री शैवाल से निकलेगा प्लास्टिक बोतलों की समस्या का समाधान

लंदन। एजेंसी

प्लास्टिक के पैक में खाने-पीने की सामग्री परोसने के खतरों से निजात पाने के लिए दुनियाभर में लगातार शोध हो रहे हैं। वैज्ञानिक व उद्यमी इसके विकल्प तलाश रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में हैदराबाद के नारायण पीसपति ने मोटे अनाज के आटे से खाने में इस्तेमाल होने वाला चम्मच बनाया है, जिसे खाना समाप्त करने के बाद थाली में रखने की जरूरत नहीं है। मतलब, चम्मच भी भोजन का हिस्सा ही है।इसी तरह, ब्रिटेन के एक स्टार्ट-अप ने समुद्री शैवाल से पानी का बरतन यानी जलपात्र बनाया है।

वहां के अखबार 'गार्जियन' की रपट में कहा गया कि यह प्लास्टिक की वैश्विक समस्या का समाधान बन सकता है। इसी तरह, दुनियाभर में ऐसे ही कई प्रयोग हो रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने बोतलबंद पानी में प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों के मौजूद होने की बात सामने आई थी, जिससे उपभोक्ताओं की सेहत पर गंभीर खतरा होने की बात कही गई थी। ब्रिटेन की एक कंपनी ने पिछले साल सितंबर में समुद्री शैवाल से निर्मित पैकेजिंग सामग्री में बर्गर या नूडल को पैक करने की तरकीब निकाली थी। वहीं, न्यूयॉर्क की एक कंपनी ने एक ऐसा कप बनाया है, जिसे आप खा सकते हैं। यह समुद्री घास व शैवाल से निर्मित है।

पोलैंड की एक कंपनी ने गेहूं की भूसी से प्लेट बनाया है, जिसे आप खा सकते हैं।

गौरतलब है कि न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कई ब्रांड्स के 27 लॉट में से 259 बोतलों का टेस्ट किया था। इसके लिए दिल्ली, चेन्नई, मुंबई समेत दुनिया के 19 शहरों से नमूने लिए गए थे। इनमें प्लास्टिक के पार्ट्स पाए गए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आई इस रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्चर्स को टेस्ट के दौरान एक लीटर की बोतल में 10.4 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स मिले। यह नल के पानी में पाए गए प्लास्टिक कणों की तुलना में दोगुना है।टेस्ट के लिए भारत समेत 9 देशों से बोतलबंद पानी के नमूने लिए गए थे। इनमें भारत के अलावा अमेरिका, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, केन्या, लेबनान, मैक्सिको और थाईलैंड शामिल हैं। इस दौरान कुल 93% नमूनों में प्लास्टिक के अवशेष पाए गए थे।

पांच राज्यों में अंदरुनी व्यापार के लिए E-WAY बिल 15 अप्रैल से जरुरी

नई दिल्ली। आईपीटी न्यूज

उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत पांच राज्यों के भीतर एक जगह से दूसरे जगह पर कारोबार-व्यापार के लिए सामाने लाने-ले जाने के लिए 15 अप्रैल से ई-वे बिल जरुरी होगा। कर्नाटक में ये व्यवस्था पहले से ही लाग हो चुकी है। पूरे देश को एक बाजार बनाने वाली कर व्यवस्था वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी में कर चोरी रोकने के लिए ई वे बिल व्यवस्था का शुरुआत की गयी है। पहली अप्रैल से जमीन, आसमान या पानी, किसी भी रास्ते से एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये या उससे ज्यादा का माल लाने-ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यानी ई वे बिल पहली अप्रैल से जरुरी कर दिया गया है जबकि 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से राज्य के भीतर ई-वे बिल शुरु करने की योजना बनायी गयी।ताजा ऐलान इसी योजना का एक हिस्सा है।

ई-वे बिल, दरअसल, एक तरह का परमिट है जो ये जानकारी देता है कि तय कीमत का माल पूरी तरह से कर चुकाने के बाद एक जगह से दूसरे जगह पर कानूनी तरीक से ले जाया जा रहा है। अभी ये व्यवस्था दो राज्यों के बीच शुरु की गयी है, जबकि कुछ दिनों बाद चरणबद्ध तरीके से राज्यों के बीच एक जगह से दूसरे जगह के बीच सामान लाने-ले जाने के मामले में इस्तेमाल होगा। ई वे बिल को कुछ हद तक पुराने समय के सी फॉर्म के तौर पर देखा जा सकता है। सी फॉर्म राज्यों के बीच कारोबार के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमे भारी गड़बड़ी होती रही और एक ही सी फॉर्म पर कई बार सामान इधर से ऊध? कर कर की चोरी की गयी. लेकिन ई वे बिल के साथ ये मुमिकन नही. इसका इस्तेमाल एक ही बार हो सकेगा। राज्यों के भीतर ई वे बिल की व्यवस्था के तहत जब कोई ट्रांसपोर्टर 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक सामान पहुंचाता है और सामान की कीमत कर सहित 50 हजार रुपये या उससे ज्यादा है तो वहां पर ई वे बिल जारी करना जरुरी होगा. हालांकि अगर उत्पादन स्थल यानी प्लांट से ट्रांसपोर्टर के यहां सामान ले जाना है और इन दो स्थानों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर से ज्यादा है तभी वहां पर ई वे बिल जारी करना जरुरी होगा

वित्त मंत्रालय GSTN को 100 फीसद सरकारी कंपनी बनाने को तैयार

जीएसटी काउंसिल करेगी अंतिम फैसला

नई दिल्ली। आईपीटी न्यूज

केंद्र सरकार जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी बनाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का आईटी ढांचा तैयार किया है। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों के जरिए सामने आई है। जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएगा और फिर जीएसटीएन एक सरकारी कंपनी बन जाएगी।

वर्तमान में, निजी वित्तीय संस्थाएं 51 फीसद हिस्सेदारी के साथ जीएसटीएन में बहुसंख्यक हिस्सेदारी रखती हैं,जबकि इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 49 फीसद की है। सूत्र के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त सचिव हसमुख अढिया से कहा है कि वो जीएसटीएन को बहुसंख्यक सरकारी कंपनी या 100 फीसद सरकारी कंपनी में परिवर्तित करने की संभावनाओं की जांच करें। सरकार अब कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के बारे में सोच रही है क्योंकि पोर्टल टैक्स संग्रह में स्थिरता आने के साथ साथ और ई-वे बिल के सफल कार्यान्वयन के साथ पूरी तरह से तैयार है। आधिकारिक सूत्र ने आगे बताया कि सरकार ने जीएसटीएन में अपनी हिस्सेदारी 49 फीसद रखी थी और इसका गठन एक निजी कंपनी के तौर पर किया था। साथ ही जीएसटी रोलआउट से पहले 'आईटी बुनियादी ढांचे के समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने' के लिए जीएसटीएन को 'पर्याप्त स्वतंत्रता' भी उपलब्ध करवाई गई थी। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर को पूरे देश में एक जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था और इसी नियम के अंतर्गत ई-वे बिल (राज्यों के बीच) को भी 1 अप्रैल 2018 से देश भर में लागू किया जा चुका है। वहीं राज्यों के बीच इसे 15 अप्रैल से लागू किए जाने की तैयारी भी की जा चुकी है।

पेट्रोल-डीजल पर मिलेगी एक रुपये की राहत

कच्चा तेल 71 डॉलर प्रति बैरल के पार

नई दिल्ली। एजेंसी

इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 71 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने के बीच केंद्र सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक रुपये प्रति लीटर खुद वहन करने के लिए कहा है। पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती को लेकर सरकार ने कुछ नहीं कहा है।

मिलेगी थोड़ी सी राहत

सरकार के इस कदम से आम आदमी को थोड़ी सी राहत मिलने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल-डीजल की कीमतें इस वक्त पिछले 4.5 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर हैं। इसमें अभी राहत मिलने की संभावना भी कम है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

सीरिया और ट्रेड वॉर से पड़ा असर

ब्रेंट क्रूड करीब 4 परसेंट चढ़कर 71 डॉलर के पार निकलने में कामयाब रहा। दरअसल अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वॉर घटने से क्रूड के भाव चढ़े हैं। साथ ही अमेरिका के सीरिया पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की अटकलों ने भी क्रूड में आग लगाई है। वहीं सऊदी अरब क्रूड के दाम 80 डॉलर तक चाहता है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड 0.25 फीसदी गिरकर 70.9 डॉलर पर कारोबार कर रहा है।

शेयर में 5 फीसदी से अधिक की गिरावट

सरकार द्वारा यह आदेश देने के बाद तेल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में 5 फीसदी से अधिक की गिरावट देखी गई। इंडियन ऑयल का शेयर 170 रुपये आ गया, जबकि भारत पेट्रोलियम का शेयर 4.5 फीसदी गिर कर के 431 रुपये पहुंच गया। सबसे ज्यादा गिरावट हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयरों में देखी गई, जो 6 फीसदी टूटकर 340 रुपये के स्तर पर आ गया है।

RBI की रोक के बाद, भारत छोड़ने की तैयारी में बिटकॉइन एक्सचेंज

मुंबई । आईपीटी न्यूज

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब से बैंकों के क्रिप्टोकरंसी में डीलिंग करने पर रोक लगाई है तब से जेबपे, यूरोकॉइन, कॉइनसिक्योर, बाययूकॉइन और बीटीसीएक्स इंडिया सहित बहुत से बिटकॉइन एक्सचेंज अपना मुख्यालय भारत से बाहर ले जाने की संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। बहुत से बिटकॉइन एक्सचेंज ने अपने अडवाइजर्स से सलाह मशविरा करना शुरू कर दिया है और वे कई तरह के टैक्स स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। ज्यादातर एक्सचेंज यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या वे अपना बेस सिंगापुर, डेलावेयर या बेलारूस जैसे देशों में शिफ्ट कर सकते हैं?

बैंकिंग रेग्युलेटर ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को बैंकों से उन ऐंटिटीज या इंडिविजुअल्स को कोई भी सर्विस नहीं देने के लिए कहा था, जो वर्चुअल करंसी में डील करते हैं या फिर उसमें सेटलमेंट करते हैं। इस घोषणा के चलते कई इन्वेस्टर्स में क्रिप्टोकरंसी बेचने की होड़ मच गई है।

ज्यादातर क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज को इस बात का डर सता रहा है कि आरबीआई का ऐलान उनके कारोबार पर ताला लगा सकता है और उनके लिए देश में कामकाज चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्रिप्टोकरंसी वॉलिट और एक्सचेंज बाययूकॉइन के सीईओ शिवम ठकराल ने कहा, 'हमें अपनी कंपनी को ऐसे देश में ले जाना होगा, जहां का कानून बैंक खाता खोलने की इजाजत हो और जहां सिर्फ कागजी करंसी में डील करना जरूरी नहीं हो।'

ये एक्सचेंज देश में कामकाज बंद करने से पहले मौजूदा कस्टमर्स का अकाउंट सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सचेंजों का मानना है कि अगर वे अपना हेडक्वॉर्टर और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट किसी अन्य देश ले जाते हैं तो भारत के कुछ कानून उन पर लागू नहीं होंगे। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट टैक्स का एक कॉनसेप्ट है, जिसके तहत

यह तय होता है कि किस देश को संबंधित एंटिटी से टैक्स वसूलने का अधिकार है।

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सचेंजों के पास दो ही रास्ते होंगे, या तो वे बिजनस बंद करें या किसी दूसरे देश में उसे ले जाएं। ग्रांट थॉर्नटन अडवाइजरी के डायरेक्टर रियाज थिंगना ने कहा, 'एक्सचेंजों के विदेश में शिफ्ट होने पर भी भारतीय निवेशक इनोवेटिव स्ट्रक्चर के जरिए उनके मार्फत वर्चुअल करंसी में निवेश जारी रख पाएंगे। हालांकि, इससे भारत में वर्चुअल करंसी ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम होगा, लेकिन यहां के बिजनस से होने वाले मुनाफे पर शायद टैक्स ना लगे क्योंकि इनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट विदेश शिफ्ट हो चुका होगा।'

इन एक्सचेंजों को सिर्फ आरबीआई से ही दिक्कत नहीं हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग और अप्रत्यक्ष कर विभाग की वजह से भी उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। आयकर विभाग ने करीब 5 लाख निवेशकों को नोटिस जारी किया था।

ईटी ने दिसंबर में खबर दी थी कि अप्रत्यक्ष कर विभाग ने भारत में काम करने वाले बिटकॉइन एक्सचेंजों की इसलिए जांच शुरू की है ताकि उन पर किस रेट से जीएसटी लगाना है, यह तय किया जा सके। पिछले वित्त वर्ष में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट और वैट अथॉरिटीज ने बिटकॉइन पर टैक्स लगाने को लेकर जांच शुरू की थी।

सूत्रों ने बताया कि हालिया सख्ती के बाद जहां इनमें से कुछ एक्सचेंजों ने अपने अडवाइजर्स से कानूनी राय मांगी है, वहीं दूसरे एक्सचेंज विदेश जाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का कहना है कि ज्यादातर बिटकॉइन एक्सचेंजों को पहले से बैन लगाए जाने की आशंका थी। इसलिए उन्होंने पहले से ही देश से बाहर मौजूदगी बना ली थी।

ब्लॉक चेन कंसल्टेंसी, ब्लॉक नेक्स्ट सॉलूशंस के फाउंडर सिद्धार्थ सोगनी ने कहा, 'अधिकतर भारतीय एक्सचेंजों ने सिंगापुर और अमेरिका में कंपनी खोल रखी है। भले ही उन्हें विदेश जाना पड़ रहा हो, लेकिन कोई भी क्लाइंट उनकी वेबसाइट यहां से एक्सेस करके क्रिप्टो टु क्रिप्टो ट्रेड कर सकता है।' ब्लॉक नेक्स्ट कंपनियों को क्रिप्टोकरंसी में निवेश करने में मदद करती है।

राष्ट्रमंडल देशों में सबसे ज्यादा FDI पाने वाला देश भारत

लंदन। एजेंसी

राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में एक दूसरे के यहां निवेश के मामले में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला है। साथ ही 53 देशों के इस संगठन में ब्रिटेन के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक निवेश आर्किषत करने वाला देश है। हाल ही में आई एक नई व्यापार समीक्षा में यह बात सामने आई है। इस रिपोर्ट को अगले हफ्ते होने वाली राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुखों की बैठक (चोगम) से पहले जारी किया गया है।

''राष्ट्रमंडल व्यापार समीक्षा 2018- राष्ट्रमंडल के लाभों का मजबूतीकरण'' को राष्ट्रमंडल सचिवालय ने तैयार किया है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि राष्ट्रमंडल के भीतर सेवाओं के व्यापार में भारत पांच सबसे शीर्ष देशों में से एक है। इस मामले में उसने कनाडा को इस मामले में पछाड़ दिया है। इसके अलावा इनमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से 2016 के बीच राष्ट्रमंडल देशों से एफडीआई पाने वाला भारत शीर्ष देश रहा। यह निवेश एकदम नए सिरे से किया जाने वाला निवेश है। इतना ही नहीं यह राष्ट्रमंडल देशों के अलावा दुनिया के अन्य देशों से भी सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाला देश रहा है। वर्ष 2015 में यह चीन को पछाड़कर नए सिरे एफडीआई पाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया।

नए सिरे से किए जाने वाले एफडीआई से तात्पर्य ऐसे निवेश से है जहां कोई कंपनी या सरकार किसी देश में नई सुविधाओं का निर्माण करके नए उपक्रम की स्थापना करती है।

पैनासोनिक ने लॉच किये नये कैमरे

नयी दिल्ली। डिजिटल इमेजिंग उत्पाद बनाने वाली कंपनी पैनासोनिक इंडिया ने डिजिटल सिंगल लेंस मिररलेस (डीएसएलएम) श्रेणी में नया लुमिक्स जी 7 और जी 85 कैमरा लॉच करने की घोषणा की है जिसकी कीमतें 53,990 रुपये से लेकर 72,990 रुपये तक है।

कंपनी के डिजिटल इमेजिंग के उत्पाद प्रमुख गौरव घवरी ने आज यहां इन कैमरो को लॉच करते हुये कहा कि फिल्मांकन, यूट्यूब और स्टिल फोटोग्राफी के लिए वीडियो गुणवत्ता की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से इनका डिजाइन किया गया है। ये लाईटवेट कैमरा 4के वीडियो रिकॉर्डिंग एवं एडिटिंग क्षमताओं से सुसज्जित हैं। उन्होंने कहा कि लुमिक्स जी85 का वजन 435 ग्राम है तथा यह यात्रा, ट्रैकिंग, वाईल्डलाईफ एवं एडवेंचर आदि में ले जाने के लिए बहुत ही आसान है। लुमिक्स जी 7 का वजन 360 ग्राम है तथा यह यूट्यूब देखने वालों, फिल्म निर्माताओं तथा वीडियोग्राफरों को एडिटिंग का अनुभव भी प्रदान करता है। लुमिक्स जी 85 की कीमत 72,990 रुपये, लुमिक्स जी की कीमत 53,990 रुपये तथा लुमिक्स जी 7 ड्युअल किट विकल्प के साथ 58,990 रुपये है।

भारत ने UN में कहा, विकास की राह में गंभीर चुनौती है अनियोजित शहरीकरण

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एक सत्र के दौरान कहा कि अनियोजित शहरीकरण और प्रवास के कारण मूल-भूत सेवाएं मुहैया कराने तथा जीवन यापन के हालातों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सत्र के दौरान भारत ने सतत/धारणीय शहरों और लोगों के एक से दूसरे स्थान पर जाकर बसने के मुद्दों पर व्यापक दृष्टिकोण रखने का आह्वान किया।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पौलोमी त्रिपाठी ने 'जनसंख्या एवं विकास आयोग' के 51 वें सत्र में कल यहां कहा कि दुनिया की आबादी का आधा से अधिक हिस्सा शहरी इलाकों में रहता है और 2050 तक इसके दो तिहाई स्तर को पार कर जाने की संभावना है। उन्होंने कहा, ''मानव इतिहास में आज से पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने मातृ देश या मूल स्थान से बाहर नहीं रहे। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से अधिकांश शहरी इलाके में रहते हैं और काम करते हैं। पूंजी, प्रौद्योगिकी, वस्तु एवं सेवाओं और लोगों की गतिशीलता भूमंडलीकरण के इस युग की विशेषताएं परिभाषित कर रही हैं।'' 'धारणीय शहर, मानव गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास' विषय पर आयोजित सत्र में उन्होंने कहा, ''इसलिए शहरीकरण अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है।'' पौलोमी ने कहा कि स्थायी शहरों और मानव गतिशीलता के मुद्दों से निपटने के लिए एक व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रवास के कारण शहरी इलाकों में नए विचार, ऊर्जा और सांस्कृतिक विविधता आती है जबकि 'अनियोजित शहरीकरण और प्रवास के कारण सेवा मुहैया कराने और रहने की स्थितियों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।' उन्होंने कहा, ''समस्या तब ज्यादा गंभीर होती है अगर प्रवास अलगाव के उच्च स्तरों पर होती है और मेजबान समुदाय के पास उसे समायोजित करने की समस्या होती है।''

रिशद प्रेमजी बने नॉस्कॉम के चेयरमैन केवश मुरुगेश होंगे वाइस चेयरमैन

नई दिल्ली। एजेंसी

आईटी इंडस्ट्री बॉडी नॉस्कॉम ने मंगलवार को विप्रो के चीफ स्ट्रैटजी ऑफिसर और बोर्ड मेम्बर रिशद प्रेमजी को 2018-19 के लिए अपना चेयरमैन बनाया है। इसके अलावा नॉस्कॉम ने ए ग्रुप के सीईओ केशव मुरुगेश को इसी अवधि के लिए वाइस चेयरमैन नियुक्त किया। नैस्कॉम पूरी दुनिया में आईटी कंपनियों के हितों के लिए काम करता है। बता दें, रिशद प्रेमजी विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी के बेटे हैं।

नॉस्कॉम की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रेमजी नॉस्कॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेम्बर रहे हैं और 2017-18 में वाइस चेयरमैन थे। रिशद प्रेमजी रमन रॉय की जगह लेंगे। रॉय क्वाट्रो ग्लोबल सर्विसेज के सीएमडी हैं। इस नियुक्त पर रिशद प्रेमजी का कहना है, नॉस्कॉम लीडरशिप टीम के भरोसा पाकर मुझे खुशी है। हम सभी डिजिटल ट्रांसफार्मेशन के अहम पड़ाव पर खड़े हैं। नॉस्कॉम प्रेसिडेंट देबजानी घोष का कहना है कि नई एनर्जी और यूनिक प्रतिभा के साथ रिशद इंडस्ट्री को आगे ले जाने में सफल होंगे।

नई लीडरशिप का फोकस टैलेंट के ग्लोबल फ्री मूवमेंट, इमिग्रेशन को लेकर इंडस्ट्री में फैले भ्रम को दूर करना और इंडस्ट्री को नई डोमेन और सीमाओं में विस्तार कराने के लिए नए व इमर्जिंग मार्केट को शामिल करने पर होगा। नई टीम इंडस्ट्री में टैलेंट के स्किल और रि-स्किल पर भी काम करेगी। बता दें, नैस्कॉम की 2500 आईटी कंपनियां सदस्य है। इसमें भारतीय और विदेशी दोनों तरह की कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां 40 लाख लोगों को रोजगार देती हैं।

कौन है रिशद प्रेमजी?

रिशद प्रेमजी अभी तक विप्रो के चीफ स्ट्रैटजी आफिसर के ओहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने साल 2007 में बिजनेस मैनेजर के रूप में विप्रो को ज्वाइन किया। रिशद प्रेमजी ने हॉवर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया है। रिशद प्रेमजी विप्रो में मर्जर और एक्विजिशन का काम देखते हैं। उन्होंने स्टार्टअप में निवेश के लिए 10 करोड़ डॉलर का फंड बनाया है। विप्रो में काम शुरू करने से पहले वो बेव कंपनी लंदन में काम करते थे। उन्होंने जीई कैपिटल के साथ भी काम किया है। 2014 में उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया था।

चौथी औद्योगिक क्रांति में बड़ी भूमिका निभा सकता है भारतः WEF चीफ

नई दिल्ली। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्ज ब्रेंदे का मानना है कि भारत चौथी वैश्विक औद्योगिक क्रांति को आकार देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है क्योंकि इसकी आधी से अधिक जनसंख्या की उम्र 27 साल से कम है। ब्रेंदे का कहना है, 'चौथी औद्योगिक क्रांति से भारत विकास के पारंपरिक चरणों में छलांग लगाते हुए विकसित देशों की श्रेणी की ओर तेजी से बढ़ सकता है।'

WEF चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर एक आलेख में यह बात कही है। इसमें उन्होंने लिखा है कि भारत की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी 27 साल से कम आयु वर्ग की है इसलिए भारत वैश्विक चौथी औद्योगिक क्रांति को आकार देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उल्लेखनीय है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन्स व इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी प्रौद्योगिकियों से हासिल होने वाली उपलब्धियों को मिलाकर चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है।

ब्रेंदे का कहना है कि इन प्रौद्योगिकियों को उचित व रणनीतिक ढंग से अपनाए जाने से संसाधन व बुनियादी ढांचे का ऐसा मिश्रण पैदा होगा जो कि बेहतर गुणवत्ता व अधिक टिकाऊ विकास की राह खोलेगा। स्टार्टअप इंडिया व अटल नवोन्मेष मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारत ने जरूरी ढांचागत सुधारों की दिशा में पहले ही उचित कदम उठाए हैं।

PAN फॉर्म में ट्रांसजेंडर के लिए होगी अलग कैटेगरी

नई दिल्ली। आईपीटी न्यूज

पर्मानेंट अकाउंट नंबर पैन बनवाने वाले ट्रांसजेंडर्स को अगल जेंडर कैटेगरी का अप्लीकेंट माना जाएगा। सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स नियम में संशोधन किया है। अभी तक पैन के लिए

अप्लीकेशन फॉर्म में केवल दो ही जेंडर पुरुष और स्त्री कैटेगरी होती थी। बता दें, टैक्स संबंधी ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर होना जरूरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सी.बी.डी.टी. ने सोमवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें ट्रांसजेंडर्स को पैन के लिए अप्लीकेशन फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स मिलेगा। यह नोटिफिकेशन इनकम टैक्स कानून की धारा 139ए और 295 के तहत जारी किया गया है। इसमें पैन नंबर के लिए नया अप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है।

ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी को होगी सहूलियत

सी.बी.डी.टी. के एक सीनियर अफसर ने बताया कि इस संबंध में बोर्ड को कुछ सुझाव मिले थे। जिसके बाद टैक्स नियमों में संशोधन किया गया। उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को पैन कार्ड बनवाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती थी और यह समस्या और गहरा गई थी जब आधार में थर्ड जेंडर का प्रावधान किया गया था लेकिन पैन में नहीं था। इसलिए ट्रांसजेंडर आधार से अपना पैन लिंक करने में सक्षम भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि अब नया बदलाव फॉर्म 49 ए भारतीय नागरिकों के लिए पैन अप्लीकेशन फॉर्म में दिखाई देगा।

सीआईसी ने दिया निर्देश, आधार लिंकिंग के कारण पेंशन भुगतान में न हो देरी

नई दिल्ली। आईपीटी न्यूज

आधार लिंक कराने को लेकर परेशान हो रहे पेंशनभोगियों के लिए राहतभरी खबर है। केंद्रीय सूचना आयोग (एच्) ने मंगलवार को कहा कि आधार जोड़ने के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों को पेशन के भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने यह व्यवस्था अहमदनगर निवासी निर्मला निशिकांत धुमाने की याचिका पर दी। धुमाने जानना चाहती थीं कि डाक विभाग ने मार्च 2017 से उनकी पेंशन आधार कार्ड की प्रति मांगते हुए क्यों रोक रखी है?

एक अन्य आवेदन में उन्होंने उन आदेशों की प्रति मांगी जिनके तहत पेंशन के लिए आधार को खाते से जोड़ना अनिवार्य किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में केंद्र सरकार के 61.17 लाख पेंशनभोगी हैं। वहीं, डाक विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दावा किया कि पेंशन रोकी नहीं गई है बल्कि पेंशन को खाते में डालने में देरी हुई है।

अधिकारी ने उच्च अधिकारियों के 15 ऐसे आदेशों का हवाला दिया जिनमें पेंशनभोगियों के खातों को उनके आधार से जोड़ने को कहा गया है। आचार्युलु ने कहा, 'आधार को जोड़ने के नाम पर या किसी अन्य हालात में , अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में देरी नहीं कर सकते।' उन्होंने कहा कि अगर खातों को आधार से जोड़ना जरूरी है तो इसके कारण पेंशन भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए और न ही पेंशन से जुड़ी सूचना से इनकार किया जाना चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर निर्भरता को भी रेखांकित किया है। आचार्युलु ने स्पष्ट किया कि लोक सेवक का वेतन ब्योरा उसकी व्यक्तिगत सूचना नहीं है बल्कि आरटीआई कानून के तहत हर कार्यालय को इसका अनिवार्य रूप से खुलासा करना चाहिए।

भारत को बिजनस के संचालन का प्रमुख केंद्र क्यों बनाने लगी हैं मल्टिनैशनल कंपनियां?

बेंगलुरु। एजेंसी

फॉर्चून 500 कंपनियों के आकर्षण का केंद्र अब भारत बन रहा है और ये कंपनियां अपना सेंटर भारत में शिफ्ट कर रही हैं। यही नहीं ये कंपनियां अपने भविष्य की रणनीतियां भी भारत में ही खोज रही हैं। यह कहना है नेवी से रिटायर्ड Ansr चलाने वाले ललित आहूजा का।

बेंगलुरु में आहूजा की कंपनी मल्टिनैशनल कंपनियों को भारत में इंजनियरिंग और रिसर्च डिवेलपमेंट सेंटर्स बनाने में मदद कर रही हैं। ऐसे कंपनियों को ग्लोबल इनहाउस सेंटर्स या जीआईसी कहा जाता है।

आईटी कंपनी नैस्कॉम के हेड के एस विश्वनाथन ने कहा, 'केवल पैसा बचाने के लिए ये कंपनियां भारत नहीं आ रहीं। वे डिजिटल टेक्नॉलजी की वजह से भारत का रुख कर रहीं हैं।' भारत में करीब 1,150 MNCs के ग्लोबल इन-हाउस सेंटर्स है जो देश के 8 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं।

सालों तक भारत को सस्ता होने के कारण आउटसोर्सिंग का केंद्र माना जाता था। आजकल ज्यादा काम डेटा-ऐनालिटिक्स, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और रोबॉटिक्स पर हो रहा है। नई डिजिटल टेक्नॉलजी बिजनस बढ़ाने में मदद कर रही हैं, जिससे MNCs के रेवेन्यू का नया सोर्स तैयार हो रहा है। इससे न सिर्फ कॉस्ट कम हो रही है बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है।

उदाहरण के लिए अडोबी के कुछ खास बड़े प्रॉडक्ट्स जैसे- एक्रोबैट, इनडिजाइन पूरी तरह से भारत के बाहर बनते हैं। फायट क्रिसलर, जीएम, फॉक्सवैगन, ¢etbow और टाटा मोटर्स के कार टेक्नॉलजी सिस्टम भारत में हार्मन रिसर्च सेंटर पर तैयार होते हैं।

मल्टिनैशनल कंपनियों की नजर बेंगलुरु पर 80 के दशक में पड़ी। अमेरिका की चिप डिजाइन फर्म टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स ने 1985 में बेंगलुरु में आरऐंडडी सेंटर स्थापित किया लेकिन 2000 के बाद आईटी सेक्टर ने बेंगलुरु में रफ्तार पकड़ी। विदेशी कंपनियों को तकनीक और इनोवेटिव सॉलूशंस के लिए भारत से ही इंजिनियर्स मिल सकते थे जिनमें क्विलिटी भी हो और कॉस्ट भी कम रहे। अभी तक कंपनियां आईबीएम, अक्सेन्चर, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों से टेक्नॉलजी आउटसोर्स करतीं थीं। ग्लोबल कंपनियां अब ये काम जीआईसी के जरिए करना शुरू कर दिया है।

बेंगलुरु के आईटी हब बनने में इंडियन इंस्टिट्यूट साइंस ने बुनियाद रखी। अब बेंगलुरु में हर बड़ी विदेशी कंपनी का ऑफिस है। नेटऐप इंडिया की डायरेक्टर एचआर सोनाली डे सरकार बताती हैं, 'हमारी भारत की साइट दुनिया में सबसे बड़ी है। हाल यह है कि अमेरिका में लोग यहां रिपोर्ट करते हैं।' मर्सेडीज बेन्ज आरऐंडडी के एमडी मनु साले ने बताया, 'चीन में भी भारत जैसा टैलंट नहीं है। चीन के लोग लोकल मार्केट पर फोकस रखते हैं।

भारत वैश्विक कदम उठाता है। मैंने इस तरह का इंटरनैशनल माइंडसेट और इंजिनियरिंग स्किल्स नहीं देखीं हैं।'

ई-आधार के लिए नया क्यूआर कोड, फोटो भी शामिल

नई दिल्ली। आईपीटी न्यूज

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ई-आधार के लिए एक नया क्यूआर कोड शुरू किया है। इस क्यूआर कोड में अब आधार धारक की जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ साथ-साथ फोटो भी होगी। आधार जारी करने वाले इस प्राधिकरण ने एक बयान में कहा है कि उसने ई-आधार पर मौजूदा क्यूआर कोड की जगह नया क्यूआर कोड शुरू किया है।

अब तक इस कोड में केवल आधार धारक से जुड़ी जानकारी होती थी। नए कोड में उसकी फोटो भी होगी। गौरतलब है कि क्यूआर कोड बारकोड लेबल का ही एक रूप है जिसमें छुपी सूचनाओं को मशीन पढ़ सकती हैं। ई-आधार, 12 अंकों की विशेष संख्या का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जिसे यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्राधिकरण का कहना है कि बैंक जैसे संस्थान अब आधार कार्ड का वेरीफिकेशन ऑफलाइन भी कर पाएंगे। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण ने कहा, 'यह आधार कार्ड के त्वरित सत्यापन का सरल 'ऑफलाइन' प्रणाली है। सूत्रों के अनुसार ऑफलाइन वेरीफिकेशन की इस सुविधा से एक और विकल्प उपलब्ध होगा और यह सुनिश्चित होगा कि धारक को आधार से जुड़ी किसी सेवा से वंचित नहीं किया जाए, लेकिन संबंधित व्यक्ति की प्रमाणिकता के लिए फोटो का लगे हाथ उसके चेहरे से मिलान करना होगा। साथ ही संबंधित एजेंसी अपने यहां लागू खास प्रमाणन योजना के जरिए भी उसका सत्यापन कर सकती है। यूआईडीएआई का ई-आधार क्यूआर कोर्ड रीडर सॉफ्टवेयर 27 मार्च 2018 से वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है।

संन्यास वह घटना है, जो मनुष्य के अंतःकरण को सुंदर बना देती है। यही कारण है कि संन्यासी कभी बूढ़ा नहीं होता, वह बिना किसी साज-शृंगार के चिर-युवा रहता है।

संन्यास से मिलता है सौंदर्य

अध्यात्म

ओशो

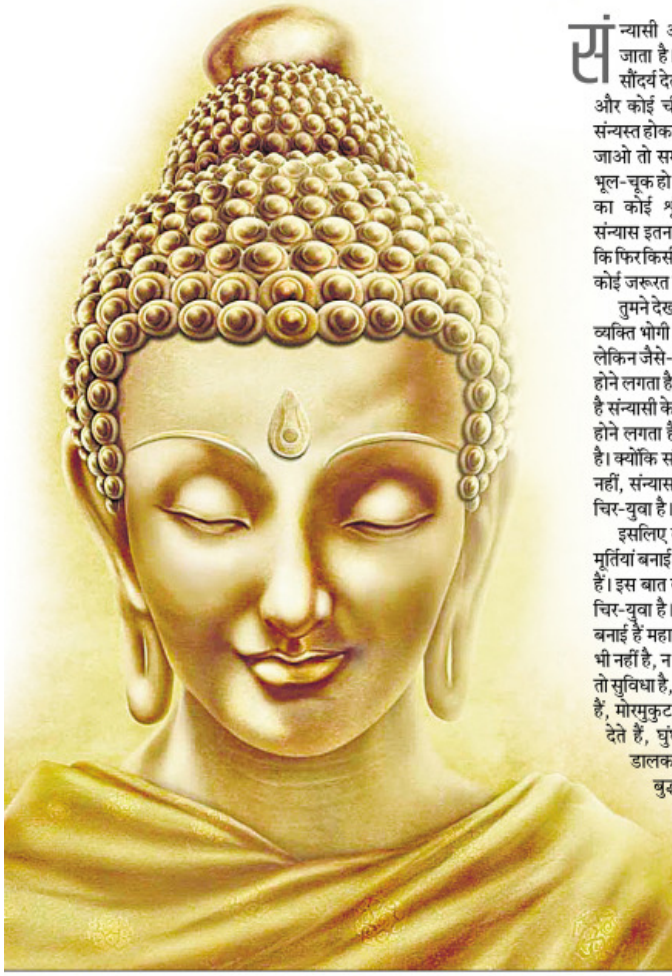

संन्यासी अपूर्व सुंदर हो जाता है। संन्यास जैसा सौंदर्य देता है, मनुष्य को और कोई चीज नहीं देती। संन्यस्त होकर तुम सुंदर न हो जाओ तो समझना कि कोई भूल-चूक हो रही है। संन्यासी का कोई शृंगार नहीं है। संन्यास इतना बड़ा शृंगार है कि फिर किसी और शृंगार की कोई जरूरत नहीं है।

तुमने देखा कि सांसारिक व्यक्ति भोगी है। जवानी में शायद सुंदर होता हो, लेकिन जैसे-जैसे बुढ़ापा आने लगता है, असुंदर होने लगता है। लेकिन उससे उलट घटना घटती है संन्यासी के जीवन में; जैसे-जैसे संन्यासी वृद्ध होने लगता है, वैसे-वैसे और सुंदर होने लगता है। क्योंकि संन्यास की कोई वृद्धावस्था होती ही नहीं, संन्यास कभी बूढ़ा होता नहीं। संन्यास तो चिर-युवा है।

इसलिए तो हमने बुद्ध और महावीर की जो मूर्तियां बनाई हैं, वह उनकी युवावस्था की बनाई हैं। इस बात की खबर देने के लिए कि संन्यासी चिर-युवा है। हमने अपूर्व सौंदर्य से भरी मूर्तियां बनाई हैं महावीर और बुद्ध की। उनके पास कुछ भी नहीं है, न कोई साज है, न शृंगार है। कृष्ण को तो सुविधा है, कृष्ण की मूर्ति को तो हम सजा लेते हैं, मोरमुकुट बांध देते हैं, रेशम के वस्त्र पहना देते हैं, घुंघरू पहना देते हैं, हाथ में कंगन डालकर मोतियों का हार लटका देते हैं, पर बुद्ध और महावीर के पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध के पास तो एक चीवर है, जिसको ओढ़ा हुआ है, महावीर के पास तो वह भी नहीं, लेकिन फिर भी अपूर्व सौंदर्य है। ऐसा सौंदर्य, जिसको किसी सजावट की कोई जरूरत नहीं।

संसार तो छोड़ना है, संसार की माया-ममता भी छोड़नी है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि संन्यास कठोर बना दे तुम्हें, कृपण बना दे तुम्हें, कि तुम्हारे हृदय को पत्थर बना दे, तब तो तुम चूक गए। अकसर ऐसा होता है। अकसर तुम्हारे तथाकथित साधु-संन्यासी और महात्मा, जिस दिन माया-मोह छोड़ते हैं, संसार का, उसी दिन दया-ममता, दया-करुणा भी छोड़ देते हैं। ये तथाकथित संन्यासी रूखे-सूखे लोग हैं। उन्होंने माया-मोह छोड़ी, उसी दिन से वे डर गए हैं। उन्होंने अपने को सुखा लिया भय के कारण। वे रसहीन हो गए हैं। उन पर न नए पत्ते लगते हैं, न नए फूल आते हैं। इसलिए तो उनके जीवन में तुम्हें सौंदर्य दिखाई न पड़ेगा। उनके जीवन में एक कुरूपता है। मरुस्थल जैसे हैं! चूक गए। रस से थोड़े ही विरोध था। पतंजलि ने कहा न- 'रसो वै सः', वह सत्य तो रसमय है, वह परमात्मा तो रस भरा है। संन्यासी रस से थोड़े ही विरुद्ध है! रस संसार में व्यर्थ न बहे, रस दया बनकर बहे, करुणा बन कर बहे, सेवा बन कर बहे; रस तुम्हें भिखारी न बनाए, सम्राट बनाए; याचक न बनाए, दानी बनाए; रस तुम लुटाओ, रस तुम दो।

> **जो संन्यास तुम्हें माया-मोह से छुड़ाकर करुणा-दया से भी दूर कर देता हो, समझना चूक गए। भूल हो गई। माया-ममता से छुड़ाने का प्रयोजन ही इतना है कि तुम्हारी जीवन-ऊर्जा करुणा बने।**

इसलिए जो संन्यास तुम्हें माया-मोह से छुड़ाकर करुणा-दया से भी छुड़ा देता हो, समझना चूक गए। तीर निशाने पर न लगा, गलत जगह लग गया। भूल हो गई। माया-ममता से छुड़ाने का प्रयोजन ही इतना है कि तुम्हारी जीवन-ऊर्जा करुणा बने। माया-ममता छूट गयी और करुणा बनी नहीं, तो संसार भी गया और सत्य भी न मिला। तुम घर के न बचे, न घाट के- तुम कहीं के न रहे। संसार छूट गया है और सत्य मिला नहीं है। बाहर का सौंदर्य छूट गया और भीतर का सौंदर्य मिला नहीं है। अटक गए। रसधार ही सूख गई। मरुस्थल हो गए। ज्यादा से ज्यादा कुछ कटि वाले झाड़ पैदा हो जाते हों मरुस्थल में तो हो जाते हों, बस और कुछ नहीं।

न ऐसे वृक्ष पैदा होते हैं कि जिनमें किसी राहगीर को छाया मिल सके, न ऐसे वृक्ष पैदा होते हैं कि रसदार फल लगें और किसी की भूख मिट सके। ना ही किसी की क्षुधा मिटती, ना ही किसी की प्यास मिटती, रूखे-सूखे ये लोग और इनकी तुम पूजा किए चले जाते हो! इनकी पूजा खतरनाक है, क्योंकि इनको देख-देखकर धीरे-धीरे तुम भी रूखे-सूखे हो जाओगे।

इस देश में यह दुर्भाग्य खूब घटा। इस देश का संन्यासी धीरे-धीरे जीवन की करुणा से ही शून्य हो गया। उसे करुणा ही नहीं आती। लोग मरते हों तो मरते रहें। लोग सड़ते हों तो सड़ते रहें। वह तो कहता, हमें क्या लेना-देना! हम तो संसार छोड़ चुके। संसार छोड़े, वह तो ठीक, लेकिन करुणा छोड़ चुके! तो फिर तुम बुद्ध की करुणा न समझोगे, महावीर की अहिंसा न समझोगे और क्राइस्ट की सेवा न समझोगे। इसे कसौटी मानकर चलना। करुणा बननी ही चाहिए। तो ही समझना कि संन्यास ठीक दिशा में यात्रा कर रहा है।

(सौजन्यः ओशोधारा, मुरथल, सोनीपत)

सत्संग पर विशेष

परमात्मा को प्रिय है सत्संग

संत राजिन्दर सिंह

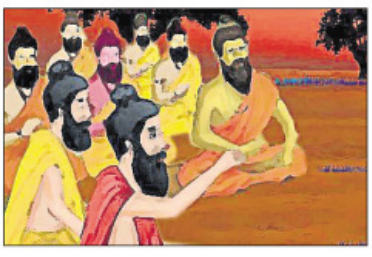

सत्संग हमें सतगुरु का दिया गया एक महान एवं बहुमूल्य उपहार है। सत्संग हमारा आध्यात्मिक विकास करता है और हमेशा हमारी सुरक्षा करता है। सत्संग के द्वारा हमें एक अभेद्य रक्षा-पंक्ति प्राप्त होती है, ताकि हम अपना ध्यान संसार की ओर से हटाकर जीवन के सच्चे लक्ष्य की ओर लगा सकें, जो है आत्म-अनुभव और प्रभु-प्राप्ति। जीवन आजकल इतना व्यस्त हो गया है कि हमारे पास आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बहुत कम समय बच पाता है। फिर भी हमसे यही कहा जाता है कि हम कम-से-कम दिन का दसवां हिस्सा, अर्थात ढाई घंटे, ध्यान-अभ्यास में बिताएं। साथ ही, यह भी कहा जाता है कि हम निष्काम सेवा में भी समय दें।

रामायण में 'लक्ष्मण-रेखा' का और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 'रामकार' की सुरक्षा का जिक्र है। संतों की छत्रछाया को रामकार कहते हैं। सत्संग में हमारे ऊपर सतगुरु की छत्रछाया होती है। सत्संग में जो पूर्ण भक्ति-भाव से जाता है, वह निस्संग हो जाता है और संसार की मोह-माया को छोड़ देता है। मोह-माया से टूटा हुआ व्यक्ति परमात्मा में दृढ़ हो जाता है। सत्संग में आकर हमें शांति व स्थिरता का अनुभव होता है। सत्संग में हमें जो उभार प्राप्त होता है, वह हमारे साथ रहता है। ऐसे में हम सांसारिक समस्याओं से परेशान नहीं होते। हमारे प्रियजन भी हमारे अंदर आए इस परिवर्तन को महसूस करते हैं। जब हम उनसे शांत व प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वे भी उसे अनुभव कर लेते हैं। यह सब हमारे सत्संग में जाने का प्रभाव होता है।

> जब हम नए-नए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब संसार के अनेक आकर्षण हम पर हमला करते हैं तब सत्संग हमारे लिए एक सुरक्षात्मक बाड़ का काम करता है।

सत्संग में हमें एक सदाचारी जीवन बिताने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग में हमें आत्मिक विकास के लिए सतगुरु का आशीर्वाद और ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमें प्रेम और आध्यात्मिक विकास से भरपूर कर देती है। सत्संग हमारे लिए एक चौकीदार का काम करता है। चौकीदार जैसे रात को 'जागते रहो' की आवाज लगाता है, उसी प्रकार सत्संग हमें इस बात के लिए जागृत करता है कि कौन से काम वास्तव में हमारी आत्मा के लिए सहायक हैं। सत्संग हमें अपना ध्यान जीवन के आध्यात्मिक पक्ष की ओर करने में मददगार होता है।

जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को हवा, जानवरों या प्रकृति की अन्य शक्तियों से नष्ट होने का खतरा होता है। उस पौधे की रक्षा के लिए हम एक छोटी-सी बाड़ लगा देते हैं। सत्संग उसी प्रकार की एक बाड़ है, जिसके द्वारा हमारा आत्मिक विकास पुष्ट होता है। जब हम नए-नए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब संसार के अनेक आकर्षण हम पर हमला करते हैं, जो हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाने में सफल हो सकते हैं। सत्संग बाड़ का काम करता है, ताकि हम आराम से ध्यान-अभ्यास कर सकें।

आस्था स्थली: गढ़ी माई, बरियारपुर, नेपाल

नेपाल का कुंभ है यह मेला

भारत में हिंदू धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा जमावड़ा कुंभ मेले के दौरान देखने को मिलता है तो वहीं नेपाल में ये जमावड़ा हर पांच साल में बारा जिले के विश्वप्रसिद्ध गढ़ी माई मंदिर में लगता है। उत्तर भारत और पड़ोसी देश नेपाल के हजारों मंदिरों में गढ़ी माई का अपना अलग स्थान है। नेपाल के बारा जिले के बरियारपुर स्थित गढ़ी माई मंदिर एक विश्वप्रसिद्ध शक्तिपीठ और सिद्धपीठ है। ये मंदिर भारतीय सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मेला बलि प्रथा के लिए अधिक प्रसिद्ध है।

क्या है मान्यता : माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना करीब आठ सौ वर्ष पहले बरियारपुर के भगवान चौधरी ने की थी। एक कथा के अनुसार, एक रात भगवान चौधरी के घर में चोरी हुई। चोर को गांव वालों ने पकड़कर सजा दी, जिसमें उस चोर की मृत्यु हो गई। इसका आरोप भगवान चौधरी पर लगाया गया और उसे काठमांडू के जेल में डाल दिया गया। जेल में ही उसे एक सपना आया, जिसमें देवी ने उससे कहा, 'किस पापी ने तुम्हें जेल में भेजा है।' भगवान चौधरी ने देवी से सवाल किया, 'आप कौन हैं। आप जो भी हैं, मेरे आगे आकर मुझे दर्शन दीजिए।' तब देवी ने उसे दर्शन दिए और कहा, 'तुम मुझे अपने गांव ले जा सकते हो' इस पर भगवान चौधरी ने कहा, 'मैं तो कैद में हूं, भला आपको गांव कैसे ले जा सकता हूं?' देवी ने कहा, 'तुम प्रतिज्ञा करो कि मुझे अपने गांव ले जाओगे तो मैं तुम्हें कैद से मुक्त कराऊंगी।' भगवती की शर्त चौधरी ने मान ली। उसके बाद सभी सिपाही निद्रामग्न हो गए और जेल का दरवाजा अपने आप खुल गया।

क्या है धार्मिक विधान : गढ़ी माई मेला पांच-पांच वर्ष में अगहन (अग्रहायण) शुक्ल पक्ष में लगता है। अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी से अष्टमी तक मंदिर में विशेष पूजा होती है। मेला मुख्य रूप से अगहन में होता है, लेकिन आषाढ़ से ही शुरू होकर फागुन तक चलता है। यहां 300 वर्षों से चल रही बलि प्रथा को नेपाल मंदिर न्यास ने अब समाप्त करने की घोषणा की है। गढ़ीमाई मंदिर में अगली पूजा 2019 में होनी है। मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन राम चंद्र शाह का कहना है, 'सबके सहयोग से हम मेले का रक्तरहित आयोजन सुनिश्चित कर सकते हैं और 2019 के गढ़ीमाई मेले को जीवन के उत्सव का प्रतीक बना सकते हैं।'

कैसे पहुंचें: नेपाल सीमा से सटे बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के रक्सौल से गढ़ी माई की दूरी 30 किलोमीटर है। वहां के लिए बस, टेम्पो, कार उपलब्ध रहते हैं। रक्सौल भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा है। हवाई मार्ग से पहुंचने के लिए नेपाल के पोखरा तक हवाई सेवा है। पोखरा से सार्वजनिक वाहन द्वारा गढ़ी माई पहुंच सकते हैं।

विशाल वैभव

भारतीय रेल को मिला सबसे पॉवरफुल इंजन, बढ़ जायेगी गाड़ियों की रफ्तार

मधेपुरा। एजेंसी

बिहार के मधेपुरा से भारतीय रेल को सबसे पॉवरफुल इंजन मिल गया। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में सत्याग्राह से स्वच्छाग्राह कार्यक्रम के दौरान रिमोट से इसका लोकार्पण किया। 12 हजार हॉर्स पावर वाले इस इंजन के साथ ही भारत अब रेल तकनीक में रूस, चीन और जर्मनी के समकक्ष पहुंच गया है। अब तक भारतीय रेल में छह हजार हॉर्स पावर का ही इंजन था। मधेपुरा निर्मित इंजन के शामिल होने के बाद मालगाड़ियों की स्पीड और माल ढुलाई क्षमता दोगुनी हो गई है।

फ्रेट कॉरिडोर में होगा इस्तेमाल

मधेपुरा में बने इंजन का इस्तेमाल गुड्स ट्रेन में किया जाएगा। ईस्टर्न-वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में रेलवे को हाई स्पीड ट्रेन चाहिए थी। मधेपुरा निर्मित इंजन ने इसकी भरपाई कर दी है। कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है।

भारत के मालगाडियों की बढ़ेगी रफ्तार

अब तक मालगाडियों की औसत रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। मधेपुरा इंजन से मालगाडियों की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। मधेपुरा में बने इंजन की अधिकतम सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है।

छह हजार टन ढुलाई की क्षमता

इस इंजन से भारी वजनी मालगाडियों को भी चलाया जा सकेगा। अब तक तीन हजार टन वजन वाली गाडियों को ही खींचा जा सकता था। इससे ज्यादा वजन के लिए दो इंजन लगाने पड़ते थे। मधेपुरा निर्मित इंजन छह हजार टन लेकर चल सकेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा है कि मधेपुरा में बनी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री और 12,000 हॉर्स पॉवर शक्ति के लोकोमोटिव इंजन का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इससे रोजगार, उद्योगों को बढ़ावा, तेज गति से माल ढुलाई, और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा।

दाम बढ़ सकते हैं दोपहिया वाहनों के: होंडा

नई दिल्ली। आईपीटी न्यूज

दो पहिया बनाने वाली कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स ने अपने वाहनों के दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। साथ ही कंपनी का कहना है कि पहली अप्रैल 2020 से ईंधन के नए मानक के अनुरुप इंजन वाले वाहन लाने जरुरी किए जाने के बाद गाड़ियों की बिक्री में कमी आ सकती है।

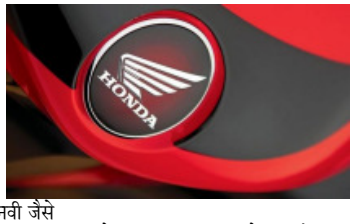

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स एक्टिवा और नवी जैसे नाम से स्कूटर बेचती है जबकि सीडी 110, साइन और एक्स ब्लेड नाम से मोटरसाइकिल बाजार में उपलब्ध है। 31 मार्च को खत्म हुए कारोबारी साल 2017-18 के दौरान कंपनी ने कुल मिलाकर 61 लाख से भी ज्यादा वाहन बेचे जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड है। कंपनी की बिक्री में 22 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ। कंपनी को उम्मीद है कि पहली अप्रैल से शुरु हुए कारोबारी साल 2018-19 के दौरान वाहनों की बिक्री में दोहरे अंक में बढ़ोतरी हासिल करने में कामयाब रहेगी।

कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यादविंदर सिंह गुलेरिया के मुताबिक, कच्चे माल और खास तौर पर धातुओं के बढ़ते दाम पर उनकी नजर है। एक सीमा तक बढ़ोतरी को खपाना संभव होगा। फिलहाल, गुलेरिया ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि किस हद तक की बढ़ोतरी के बाद वाहनों के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये जानकारी देने से भी इनकार कर दिया गया कि दाम अगर बढ़ेंगे तो भी कब और कितने। ध्यान रहे कि तमाम ऑटो कंपनियां कच्चे माल के बढ़ते दाम को लेकर चिंतित है और दाम बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही हैं।

होंडा, फिलहाल, इंधन के मानक भारत स्टैंडर्ड यानी बीएस-6 के अनुरुप इंजन वाले वाहनों को तय समय के मुताबिक बाजार में लाने की तैयारी में है. सरकारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, पहली अप्रैल 2020 के बाद बाजार में बीएस-6 मानक के अनुरुप इंजन वाले वाहन ही बाजार में बिकेंगे. ये बात अहम है कि इस नए मानक के जरिए प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी, लेकिन ग्राहक और कंपनी के लिए यहां बुरी खबर है. गुलेरिया के मुताबिक, नई तकनीक की वजह से लागत बढ़ेगी जिसका बोझ ग्राहकों को उठाना होगा. फिलहाल, अभी ये बताना संभव नहीं कि बढ़ोतरी कितनी होगी. दूसरी ओर कीमत बढ़ने की वजह से मुमकिन है कि लोग खरीदारी में कमी करे, इससे बाजार के विकास पर असर पड़ेगा. बतौर गुलेरिया, 2019 और 2020 में नई-नई तकनीक के इस्तेमाल के बाद वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वाहनो के बाजार की बिक्री की बढ़ोतरी पर ब्रेक लग सकता हैहोडा ने इस मौके पर 2018-19 की कारोबारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि वो अपने एक नया मॉडल लांच करेगी. साथ ही 18 अपग्रेड, यानी मौजूदा मॉडलों में सुधार, करेगी. कंपनी ने अपने बिक्री केंद्रो की संख्या 6000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. दूसरी ओर जो ग्राहक लगातार जुड़े रहे हैं, उनके लिए खास लॉयल्टी प्रोगाम होंडा जॉय क्लब लांच होगा.

3 टायर्स और 400CC इंजन वाला स्कूटर जल्द होगा भारत में लॉन्च, जानिए कीमत

नई दिल्ली। एजेंसी

फ्रांस की ऑटोमोबाइल कंपनी झलुदू अब जल्द ही भारत में अपना नया पावरफुल स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी भारत में नया झलुद Metropolis 400 को उतारेगी। यह स्कूटर आम स्कूटर्स की तुलना में काफी अलग होगा, खास बात यह भी है कि इसमें 2 नहीं बल्कि 2 टायर्स हैं और इसके तीनों टायर्स में डिस्क ब्रेक की सुविधा दी हैं। ऐसे में इसे राइड करना आसन होगा क्योंकि इसमें राइडर को बैलेंस मिलता है। आपको बता दे कि झलुदू महिंद्रा 2 व्हीलर के साथ काम कर रही है।

इंजन की बात करें तो झलुदा Metropolis 400 में 400cc का इंजन मिलेगा जो 35.6bhp की पावर और 28.1 Nm का टॉर्क मिलता है। इसमें 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है जोकि ठीक है, भारत से पहले इस स्कूटर को को विदेशी मार्किट में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। स्कूटर में सेमी डिजिटल मीटर दिया है। कीमत की बात करें तो झलुद Metropolis 400 की संभावित कीमत करीब 2.5 लाख रुपये हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी सही कीमत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, वैसे ह्जल्द ही इसकी कीमत के बारे में भी पता चल जायेगा। इसका वजन करीब 258 किलोग्राम है।

फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में मेंटेनेंस फ्री बैटरी, एनालॉग स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, टेम्परेटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल फ्यूल गेज, लो फ्यूल गेज, लो फ्यूल वार्निंग, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, वो बैटरी इंडिकेटर जैसे ढ़ेरों फीचर्स दिए गये हैं। भारत में यह स्कूटर 4 कलर्स में आएगा।

फिलिपींस में लॉन्च होगी भारत में बनी हुई मारुति सुज़ुकी डिज़ायर

नई दिल्ली। एजेंसी

तीसरी जनरेशन मारुति सुज़ुकी डिज़ायर ब्रिक्री के साथ लुक और फीचर्स के मामले में बेहतरीन कार साबित हुई है और भारतीय कार ग्राहकों ने इसे बेहद पसंद किया है। अब कंपनी ने इस कार को फिलिपींस में लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है और वहां कार का डेब्यू भी किया है। नई जनरेशन डिज़ायर को हाल ही में साउथ ईस्ट एशियाई बाज़ार में डेब्यू किया गया है और इस कार को मनीला इंटारनेशनल ऑटो शो 2018 में पेश किया गया था। फिलिपींस में कंपनी इस कार को 2018 के अंत तक लॉन्च कर सकती है। बता दें कि फिलिपींस में पहले से ही मारुति सुज़ुकी अपनी दूसरी जनरेशन डिज़ायर बेच रही है और भारत की तर्ज़ पर ही लॉन्च होने के बाद यह कार पुराने मॉडल को रिप्लेस करने वाली है।

अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और स्वच्छ भूमि सौंपना हमारी जिम्मेदारी : श्रीमती सुमित्रा महाजन

स्वच्छ भारत अभियान समय की मांग - श्री हरदीप सिंह पुरी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

शहरीकरण और आधुनिकीकरण विकास के लिए हमारी जरूरत है पर इसे पाने के क्रम में हमें भूमि, जल और वायु को प्रदूषण और अत्यधिक दोहन से बचाने पर भी ध्यान देना होगा। यह बात लोक सभाध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज इंदौर में भारत सरकार, जापान सरकार, संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार, इंदौर नगर निगम तथा सी आई आई के संयोजन में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र की आठवीं 3आर फोरम की तीन दिवसीय बैठक के उद्घाटन के अवसर पर कही।

श्रीमती महाजन ने कहा कि बड़ी मात्रा में उत्सर्जित हो रहे कचरे का निपटान करने के लक्ष्य को हम 3 आर यानि रिड्यूस, रियुस और रिसाइकल के मंत्र को अपनाकर प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रकृति से जितना लिया, उससे ज्यादा लौटाने के धर्म का पालन करने की हमारी संस्कृति और जैव विविधता के संरक्षण की अवधारणा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि रिड्युस का अर्थ अपना लालच, दोहन की रफ़्तार और जरूरतें कम करने से लगाया जाना चाहिए। रियुज का तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों के पुनः इस्तेमाल से है, जैसे पेयजल के पाइप के अलावा इस्तेमाल किये हुए पानी के पुनः इस्तेमाल के लिए भी एक पाइप लाइन होना चाहिए। श्रीमती महाजन ने इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए समाज और सरकार के साझा प्रयासों का उदहारण देते हुए कहा कि, घर, मोहल्ले, नगर, शहर, प्रदेश और देश को स्वच्छ बनाने के लिए जनता की सहभागिता और सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा देश को स्वच्छ बनाने के आह्वान को जनता ने दिल से स्वीकार किया है, जिसके चलते स्वच्छ भारत अभियान को अद्भुत जन सहयोग मिल रहा है। लोक सभाध्यक्ष ने कहा कि कचरा ऊर्जा उत्पादन, खाद निर्माण, सड़क निर्माण का बेहतर साधन है। हम कचरे को कचरा धन मानकर रिसाइक्लिंग करके बहुत से कामों में ले सकते है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 3 आर फोरम की तीन दिवसीय बैठक में अपशिष्ट प्रबंधन के सामाजिक, आर्थिक, और

अन्य पहलुओं पर सार्थक तथा उपयोगी चर्चा होगी।

कार्यक्रम में भारत सरकार के आवास और शहरी मामलो के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एशिया, प्रशांत क्षेत्र के विकास के लिए इंदौर में आयोजित 3 आर फोरम में प्राप्त सुझाव और जानकारियां बेहद उपयोगी साबित होंगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी ने कहा था कि स्वच्छता की प्राप्ति, राजनैतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति से भी जरूरी है। श्री पूरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिय गया 6 आर उनका मंत्रालय जल संरक्षण, सीवेज मैनेजमेंट, शौचालय निर्माण जैसे कामों के साथ जनता के व्यवहार और आदतों में बदलाव लाने पर भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें 100 प्रतिशत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लक्ष्य प्राप्त करने के सार्थक प्रयास करने होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया 6 आर रिड्यूस, रियुस, रिसाइकल, रिकवर, रिडिजाइन और रिमेनुफेक्चर का मन्त्र अपनाने पर रिजोयिस यानि परमानन्द की प्राप्ति होगी। श्री पुरी ने कहा कि कचरे से बिजली उत्पादन, खाद बनाना, सड़क निर्माण तथा अन्य कार्य करना हमारा लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने में 3 आर फोरम की बैठक में प्राप्त सुझाव और जानकारियां बेहद उपयोगी साबित होंगी।

इस अवसर पर जापान के पर्यावरण राज्य मंत्री तादाहिको ईतो ने कहा कि एशिया -प्रशांत क्षेत्र विकास के बहुत से मानदंडों पर चुनौतियाँ झेल रहा है, जिनमें कचरा प्रबंधन, भूमि, जल और वायु संरक्षण के मुद्दे खास है। उन्होंने इंदौर की स्वच्छता की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत और जापान 3 आर के बारे में एक जैसी सोच रखते हैं, जो अगली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य और संरक्षित वसुंधरा सौपने की सोच पर आधारित है। श्री ईतो ने कहा कि जापान भारत को स्वच्छता के मापदण्ड प्राप्त करने के लिए हर संभव सहयोग देगा और हम मिल जुलकर स्वच्छ भूमि, जल और वायु का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि जापान एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित सम्पूर्ण विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की आवास और शहरी विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने मध्यप्रदेश में अपशिष्ट प्रबंधन के हो रहे उल्लेखनीय कामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंदौर में कचरे से निर्माण सामग्री और खाद, जबलपुर में कचरे से बिजली और कटनी में खाद बनाई जा रही है। श्रीमती सिंह ने बताया कि कचरा प्रबंधन के लिए प्रदेश की 378 लोकल बॉडीज को 26 क्लस्टर्स में बांटा गया है जिनमें से 20 क्लस्टर्स में कचरे से खाद और 6 क्लस्टर्स में बिजली बनायेगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अगले 2-3 वर्षों में रिसाइकल की गई वस्तुओं को बाजार में प्रस्तुत करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक मामलो की अधिकारी सुश्री ब्रिजिट बेराल्ड ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, वर्ष 2030 तक उच्च जीवन स्तर, विकास, स्वच्छता के मानकों को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। जनता को स्वच्छ जल, वायु, भूमि उपलब्ध कराना जरूरी है। हमें विकास योजनाएं बनाते समय पर्यावरण की रक्षा करने का ध्यान रखना होगा। कचरा प्रबंधन के लिए हमें 3 आर फोरम में खुल कर विचारों का आदान प्रदान करना होगा। इसके पहले अपने स्वागत भाषण में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान के बाद देश में स्वच्छता की लहर चल रही है क्योंकि स्वच्छता वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथो में वर्णित हमारी जीवन पद्दति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इंदौर में आयोजित हो रही 3 आर समिट कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित होगी। तीन दिवसीय 3 आर फोरम समिट में 40 देशों के 300 प्रतिनिधि, भारत 106 शहरों के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारी और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।